तिब्बत देश

चीनी शासकों के इरादों पर तिब्बती लोकतंत्र का पानी

तिब्बती 'कालोन ट्रीपा' (प्रधानमंत्री) पद पर 43 वर्षीय डा. लोबसांग सेंग्ये के चुने जाने के साथ तिब्बत एक नए लोकतांत्रिक युग में प्रवेश कर रहा है। लेकिन 27 अप्रैल को धर्मशाला में घोषित चुनाव परिणामों में तिब्बत की 15वीं संसद के नए सदस्यों और प्रधानमंत्री पद पर हॉवर्ड लॉ स्कूल से जुड़े तिब्बती विद्वान डा. लोबसांग के निर्वाचन की घोषणा पर चीन की प्रतिक्रिया खासी नाराज़गी और गुस्से भरी रही। चीन और तिब्बत के ताज़ा इतिहास को देखते हुए चीन सरकार की यह तिलमिलाहट स्वभाविक है। बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हांग ली का कहना था, "जिस तथाकथित सरकार का वह प्रधानमंत्री चुना गया है वह खुद ही एक गैरकानूनी राजनीतिक संस्था है जिसे दलाई लामा ने तिब्बत को आजाद कराने और अलगाववादी गतिविधियां चलाने के लिए स्थापित किया है।" धर्मशाला से चलने वाली इस निर्वासन सरकार का मजाक उड़ाते हुए चीनी प्रवक्ता ने कटाक्ष किया, "और उस सरकार को दुनिया की किसी सरकार ने मान्यता नहीं दी है।"

एक तरफ तो दलाई लामा के नेतृत्व में चलने वाली निर्वासन सरकार के लिए 'तथाकथित सरकार' जैसे शब्द इस्तेमाल करके और मान्यता न होने की दुहाई देकर उसे अर्थहीन दिखाने की कोशिश करना और दूसरी ओर उसी सांस में तिब्बत की आजादी और चीन को तोड़ने जैसे मुद्दे उठाकर चीनी प्रवक्ता ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वह दलाई लामा से कितनी भयभीत है। लेकिन इस बार इस भय और तिलमिलाहट के पीछे एक ऐसा कारण है जिसने तिब्बत पर 1951 से उपनिवेशवादी कब्जा जमाए बैठे कम्युनिस्ट चीनी शासकों की नींद हराम कर दी है और उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है ।

ऐसा नहीं कि तिब्बत की निर्वासन सरकार में पहली बार चुनाव हुआ है या पहली बार कोई कालोन ट्रीपा (प्रधानमंत्री) नियुक्त होने जा रहा है। असल में 1959 में निर्वासन में आने के बाद दलाई लामा कई बार अपनी निर्वासन सरकार में प्रधानमंत्री नियुक्त कर चुके हैं और 15 बार तिब्बती शरणार्थी अपने सांसद चुन चुके हैं। बल्कि 2001 के बाद यह तीसरा मौका है जब दुनिया भर में बसे तिब्बती शरणार्थियों ने सीधे मतदान से अपने लिए नए प्रधानमंत्री का चुनाव किया है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री पद पर बैठने जा रहे डा. लोबसांग तिब्बत के इतिहास में पहले ऐसे कालोन ट्रीपा होंगे जिनकी सरकार और संसद को दलाई लामा अपनी सारी वैधानिक और राजनीतिक शक्तियां सौंपने जा रहे हैं।

दलाई लामा के इस क्रांतिकारी फैसले ने चीन के कम्युनिस्ट शासकों की उन उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है जिन्हें सीने से लगाकर वे कई दशकों से वर्तमान दलाई लामा के स्वर्गवास का इंतजार करते आ रहे थे। सन् 1642 से 1951 तक तिब्बत पर दलाई लामा के नेतृत्व में चली 'गंदेन फोड्रांग' शासन प्रणाली में दलाई लामा तिब्बत का सर्वोच्च धर्मगुरू होने के साथ–साथ वहां का राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भी होता है। हर नए दलाई लामा का चुनाव पुनर्जन्म के आधार पर किया जाता है। यानी एक दलाई लामा की मृत्यु के तीन चार साल बाद उनके नए अवतार बच्चे को गद्दी पर बिठाया जाता है और उसके वयस्क होने पर देश का शासन सौंपा जाता है। वर्तमान 75 वर्षीय दलाई लामा (निजी नाम 'तेनज़िन ग्यात्सो') इस पारंपरा में चौदहवें हैं।

अपने आधुनिक और लोकतांत्रिक क्रांतिकारी विचारों के लिए शुरू से ही चर्चित रहे वर्तमान दलाई लामा ने इस साल 10 मार्च को तिब्बत के जनक्रांति दिवस पर घोषणा की थी कि वह आने वाले चुनावों में जीतने वाले प्रधानमंत्री और संसद को अपने सारे राजनीतिक और शासकीय अधिकार सौंप देंगे और केवल धार्मिक पदवी अपने पास रखेंगे। इसके साथ उन्होंने यह इच्छा भी व्यक्त की है कि भविष्य में नए दलाई लामा की नियुक्ति पुनर्जन्म और अवतार के आधार पर नहीं बल्कि अनुभव और योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। यानि अपनी मृत्यु से पहले ही वह सुनिश्चित कर जाएंगे कि उनके स्थान पर कोई विद्वान और योग्य तिब्बती शरणार्थी 15वें दलाई लामा के पद पर बैठे।

दलाई लामा के इन दो फैसलों ने चीनी शासकों की इस उम्मीद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है कि वर्तमान दलाई लामा के मरने के तुरंत बाद वे अपनी मर्जी के किसी बच्चे को नया 'दलाई लामा' घोषित करके तिब्बत की समस्या को हमेशा के लिए हल कर लेंगे। इससे पहले 1990 वाले दशक में चीनी शासक कर्मा पा और पंचेन लामा के नए अवतारों की नियुक्ति करके अपने इस नाटक की फुल ड्रेस रिहर्सल कर चुके हैं। यह बात अलग है कि चीन के चुने गए कर्मापा छह साल बाद अचानक उनके चंगुल से भागकर भारत चले आए। जबरदस्ती पंचेन लामा बनाए गए चीनी कठपुतली को भी आज तक तिब्बती जनता ने 'पंचेन लामा' के तौर पर स्वीकार नहीं किया है। अब अगर चीनी नेता कोई नाटकबाजी करके किसी तिब्बती बच्चे को जबरदस्ती एक पिट्ठू 'दलाई लामा' घोषित कर भी लेते हैं तो दलाई लामा की असली राजनीतिक, शासकीय और धार्मिक शक्तियों से वह एकदम महरूम होगा।

चीनी नेताओं को अब समझ में आ रहा है कि अगर वे तिब्बत पर अपने उवनिवेशी शिकंजे को कसने के लिए दलाई लामा के नए अवतार का इस्तेमाल करने के मंसूबे पाले हुए थे तो दलाई लामा भी अपने देश को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए पिछले पचास साल से एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था विकसित करने में लगे हुए थे जो उनके निजी जीवन काल के बाद भी तिब्बत के मुक्ति आंदोलन को उसकी वास्तविक मंजिल तक ले जा सके। कानून और राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी 43 वर्षीय युवा डा. लोबसांग सेंग्ये के चुनाव ने तिब्बत को ऐसा नेता दिया है जो तिब्बत की आजादी के उस यज्ञ को आगे बढ़ाएगा जिसे दलाई लामा पिछले पांच दशक में इस मुकाम तक ले आए हैं। उम्मीद की जा रही है कि 15 अगस्त को नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले डा. लोबसांग तिब्बत के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू करेंगे। उनके चुनाव ने चीनी गुलामी से पीड़ित तिब्बती जनता के अलावा दुनिया भर में उन लाखों तिब्बत समर्थकों को भी आश्वस्त किया है जो दलाई लामा के लंबे जीवन की कामना के साथ यह भी सुनिश्चित देखना चाह रहे हैं कि दलाई लामा के बाद भी तिब्बती मुक्ति आंदोलन पूरे दम से कायम रहे।

– विजय क्रान्ति

भारत एवं तिब्बत पर नजर रखते हुए नेपाल में चीन के कदम

चीनी अधिकारियों ने उस कीर्ति मठ के इर्द–गिर्द सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया है जहां फुंसोक का निधन हुआ था। भिक्षुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी आवाजाही पर रोक है। सूत्रों के अनुसार 25 मार्च को करीब एक दर्जन सैन्य कर्मी मठ में घुस गए और उन्होंने तेनजिन नाम के एक 21 वर्षीय भिक्षु को हिरासत में ले लिया।

(टाइम, 29 मार्च)

जब चीन की जनमुक्ति सेना के अध्यक्ष जनरल चेन बिंगदे ने 23 मार्च को काठमांडू में कदम रखा तो उन पर पूरे नेपाल की नजरें थीं। चेन ने इस यात्रा के दौरान 2 करोड़ डॉलर के एक सैन्य सहायता सौदे पर दस्तखत किए और यह वादा किया कि चीन और भी सहायता देगा। इस मौके पर चीन–नेपाल रिश्ते पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच गठजोड़ ''विश्व शांति और एशिया–प्रशांत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण'' है। चेन की इस टिप्पणी से चीन के इस प्रयास को समझने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि वह अपने क्षेत्रीय दावे को मजबूत करना चाहता है और अपना क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाना चाहता है। हालांकि, नेपाल एक छोटा देश है, चीन इसे भारत एवं तिब्बत जैसे संवदेनशील एवं भू–सामरिक मसलों पर एक सहयोगी के रूप में देखता है। नेपाल की सरकार अपने नए संरक्षकों को गले लगाने को तैयार है। जब चेन वहां से विदा हुए तो माओवादी नेता झलनाथ खनाल ने एक बार फिर यह दुहराया कि "नेपाल की जमीन से कोई भी चीन विरोधी गतिविधि" नहीं होने दी जाएगी।

नेपाल में चीन का हित मुख्यतः भू–सामरिक ही है। काठमांडू स्थित नेपाल एवं एशियाई अध्ययन केंद्र में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ध्रुव कुमार ने बताया, "चीन ने पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर लिए हैं और अब वह भारत के पड़ोसियों बर्मा, श्रीलंका और बांग्लादेश में अपने कदम मजबूत कर रहा है। नेपाल में उसके कदम से यह पता चलता है कि यह देश उनके व्यापक सामरिक गठजोड़ के लिए लॉन्चपैड बन गया है। इससे निश्चित रूप से भारत को चिंता होगी।" नेपाल काफी हद तक भारत के आयात पर निर्भर है। दोनों देशों के बीच करीब 2 अरब डॉलर का सालाना व्यापार होता है। इसके अलावा भारत समूचे नेपाल में सैकड़ों छोटे सहायता कार्यक्रमों को भी धन देता है। स्कूल, पुस्तकालय बनाने जैसे कार्यक्रमों में भारत करीब 4 लाख डॉलर खर्च करता है। दूसरी तरफ, चीन ने भी अप्रैल, 2009 से नेपाल को दी जाने वाली वार्षिक सहायता राशि में 50 फीसदी बढ़त करके उसे 2.2 करोड़ डॉलर तक पहुंचा दिया है और इसका ज्यादातर हिस्सा बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रमों में जाता है। चीन के नए सैन्य नेतृत्व के सामने तिब्बत का मसला भी गहराया हुआ है। चेन के दौरे के ठीक पहले नेपाल ने काठमांडू में तिब्बतियों के प्रदर्शन को कुचला है। विफल तिब्बती जनक्रांति की 52वीं वर्षगांठ के अवसर पर 10 मार्च को इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों पर नेपाल की पुलिस ने धावा बोल दिया। इसके दस दिन बाद नेपाल में रहने वाले तिब्बतियों को अपने निर्वासित सरकार के लिए वोट डालने से रोक दिया गया, जबकि भारत और अन्य देशों में उन्हें वोट डालने से नहीं रोका गया। नेपाल के एक अखबार ने सेना में एक सूत्र के हवाले से खबर छापी कि चीनी प्रतिनिधिमंडल ने यह मांग की है कि उत्तरी सीमा पर सेना तैनात की जाए ताकि निर्वासित तिब्बतियों को आने से रोका जा सके, जो पकड़ कर वापस भेज दिए जाने के जोखिम के बावजूद पहाड़ी सीमा को पार कर भारत के धर्मशाला शहर पहुंच जाते हैं। इन कदमों को नेपाल में इस बात के प्रमाण के रूप में देखा जा रहा है कि काठमांडू के सत्ताधारी संभ्रात वर्ग में बीजिंग का प्रभाव बढ़ रहा है। वास्तव में मौजूदा माओवादी–एकीकृत माओवादी लेनिनवादी (एमाले) सरकार जो इससे पहले की भारत समर्थक सरकार को हटाकर सत्ता में आई है, व्यापक रूप से चीन समर्थक मानी जा रही है। कुमार का कहना है कि चीनी, नेपाल की सेना के साथ इसलिए गठजोड़ करना चाहते हैं क्योंकि, "यह एकमात्र भरोसेमंद और मजबूत संस्थान है, बेदाग और साफ और जिसमें बाहरी प्रभाव बहुत कम है।" सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी के विजिटिंग फेलो प्रोफेसर एस.डी. मुनि नेपाल में चीन के प्रभाव बढ़ाने को उसकी व्यावहारिकता बताते हैं। उन्होंने कहा, "चीन का नेपाल के साथ वैसा कोई गंभीर भावनात्मक या सांस्कृतिक जोड़ नहीं है। इसलिए वह नेपाल में खुद को वहां की नियंत्रक राजनीतिक ताकतों से ही जोड़ सकता है चाहे वह माओवादी हों या सेना।" मजबूत हिमालय कभी नेपाल और तिब्बत के बीच प्राकृतिक सीमा रहा है। लेकिन जब चीन ने पश्चिम की ओर देखना शुरू किया यह बहुत दिन तक नहीं रह पाया।

भिक्षु के आत्मदाह के बाद जारी है तिब्बत में चीनी दमन

(रेडियो फ्री एशिया, 29 मार्च)

चीनी शासन के खिलाफ एक भिक्षु द्वारा आत्मदाह कर लेने के बाद भड़क उठे विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए चीनी अधिकारियों ने 12 तिब्बतियों को हिरासत में ले लिया है। भिक्षु के आत्मदाह के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और इन प्रदर्शनों के तहत ही एक हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने भूख हड़ताल शुरू किया है। सिचुआन प्रांत के नाबा तिब्बती स्वायत्तशासी प्रशासन में 23 मार्च को 100 जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन हुए जिसमें लोग 'तिब्बत को आज़ाद करो', 'दलाई लामा को तिब्बत बुलाओ' और 'तिब्बत को मुक्त करो' जैसे नारे लगा रहे थे।

सूत्रों के अनुसार विरोध प्रदर्शनकारियों ने जामथांग (चीनी में रांगतांग) काउंटी में स्थित नाधा टाउनशिप के बाजार चौराहे का तीन बार चक्कर लगाया , इसके बाद चीनी सुरक्षा बल वहां पहुंचे, उन्होंने प्रदर्शनकारियों को पीटा और प्रदर्शन को रोक दिया। एक भिक्षु ने बताया, "सुरक्षा बलों ने आठ तिब्बतियों को हिरासत में ले लिया जिसमें नाधा टाउन के एक स्कूल शिक्षक भी शामिल हैं। चीन की जन सैन्य पुलिस के जवान शहर में गश्त कर रहे हैं और नाबा के कई दूसरे क्षेत्रों में भी सख्त निगरानी की जा रही है। वे अब भी विरोघ प्रदर्शन में शामिल तिब्बतियों की तलाश में लगे हैं।"

पिछले हफ्ते साल 2008 के नाबा के कीर्ति कस्बे में विरोध प्रदर्शनों की तीसरी वर्षगांठ के बाद यह तिब्बत में नवीनतम सरकार विरोधी प्रदर्शन हैं। कीर्ति में हुए विरोध प्रदर्शनों में चीनी पुलिस ने भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी थी जिससे कम से कम 10 तिब्बती मारे गए थे।

चीनी सुरक्षा बलों ने तीन अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है जिनमें चीनी शासन के विरोध में खुद को आग लगाकर आत्मदाह कर लेने वाले भिक्षु फुंसोक के मामा और 19 साल के भाई भी शामिल हैं। इन लोगों को फुंसोक के प्रदर्शन में सहयोग करने के संदेह में गिरफ्तार किया गया है। एक भिक्षु ने बताया, "22 मार्च को फुंसोक के 19 वर्षीय भाई एवं कीर्ति मठ के भिक्षु लोबसांग केलसांग, उनके मामा लोबसांग सोन्डु और कीर्ति मठ के एक अन्य भिक्षु सामड्रुप को हिरासत में ले लिया गया।" फुंसोक की मौत के बाद नाबा प्रशासनिक क्षेत्र के हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दिया। भिक्षु ने बताया, "चीनी अधिकारियों ने बहुत से विद्यार्थियों और शिक्षकों के मोबाइल फोन छीन लिए और उनके स्कूल के अंदर या बाहर जाने पर रोक लगा दिया गया। इसकी वजह से विद्यार्थी अपने परिवार के लोगों से बात नहीं कर पाए और अब भी वहां के हालात के बारे में कुछ नहीं पता चल पा रहा।" अभी यह पता नहीं चल पा रहा कि विद्यार्थियों की भूख हड़ताल अब भी जारी है या नहीं।

चीनी अधिकारियों ने उस कीर्ति मठ के इर्द–गिर्द सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया है जहां फुंसोक का निधन हुआ था। भिक्षुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी आवाजाही पर रोक है। सूत्रों के अनुसार 25 मार्च को करीब एक दर्जन सैन्य कर्मी मठ में घुस गए और उन्होंने तेनजिन नाम के एक 21 वर्षीय भिक्षु को हिरासत में ले लिया। सूत्र ने बताया, "इस मामले में कुछ भी पता नहीं चल पाया है कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया और कहां रखा गया है। हर रात कीर्ति मठ के आसपास पुलिस सूंघने वाले कुत्तों के साथ गश्त करते हुए दिख जाती है।" तिब्बती सूत्रों ने बताया कि स्थानीय अधिकारियों ने कीर्ति मठ के आसपास के गांवो की एक बैठक बुलाई और लोगों से कहा कि वे 'सुरक्षा ड्यूटी' के तहत मठ में पहुंचें। जो लोग इस ड्यूटी पर नहीं आते हैं उनसे हर दिन 30 यूआन (करीब 180 रुपए) का जुर्माना लिया जाता है।

यह फिल्म तिब्बती लोगों में काफी लोकप्रिय हुई है।

तिब्बती लेखक ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से किया निवेदन

(टीसीएचआरडी, 24 मार्च)

तिब्बती लेखक–आंदोलनकारी भिक्षु ल्हाडेन ने इस महीने साल 2008 की जनक्रांति की तीसरी वर्षगांठ और जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के 16वें सत्र के दौरान अपनी पुस्तक ''जान को जोखिम पर रखकर निकले शब्द'' (वर्ड्स यूटर्ड विद लाइफ ऑन रिस्क) को लोकार्पित किया।

ल्हाडेन करीब तीन साल से बेहद सतर्कता से यह पुस्तक लिख रहे थे। इस पुस्तक में उन्होंने साल 2008 में हुए जनक्रांति के कारण और परिणामों के बारे में अपने प्रेक्षण और तर्क दिए हैं। करीब 255 पेज की इस पुस्तक में पांच अध्याय हैं जिनमें विरोध प्रदर्शन, उसके कारण, संभावनाएं, दमन, चीनी विद्वानों के विश्लेषण, पुलिस की क्रूरता और दलाई लामा के बारे में सरकारी दुष्प्रचार की जानकारी दी गई है। ल्हादेन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से यह निवेदन किया है कि वह सिर्फ सुरक्षा परिषद में सीट रखने वाले देशों का भोंपू बनने या केवल आज़ाद लोगों के लिए विचार–विमर्श का मंच बनने की जगह दमित लोगों की आवाज़ को गंभीरता से सुने। उन्होंने लिखा है, "अपने जीवन को दांव पर लगाते हुए, मैं इस पुस्तक को दमितों की आवाज़ और एक निवेदन के रूप में पेश कर रहा हूं।"

गौरतलब है कि तिब्बत में साल 2008 के बाद चीनी अधिकारियों ने करीब 70 तिब्बती लेखकों, ब्लॉगर और संस्कृति कर्मियों को उनकी विषयवस्तु की वजह से प्रताड़ित किया, पीटा, हिरासत में लिया और गिरफ्तार किया है। तिब्बत में इस जनक्रांति के बाद अभिव्यक्ति और सूचनाओं की आज़ादी पर हमला और बढ़ गया है। सरकारी अधिकारी हाल के राजनीतिक अशांति को तिब्बतियों के अभिव्यक्ति के अधिकार का और गला घोंटने का एक औचित्य साबित कर रहे हैं। ये अधिकारी अस्पष्ट कानूनी प्रावधानों का फायदा उठाकर तिब्बती बुद्धिजीवियों को ''राजनीतिक रूप से खतरनाक'' बताते हुए उनके शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को भी अपराध साबित कर रहे हैं।

आधुनिक तिब्बत के इतिहासकारों के अनुसार यह ऐसी पहली घटना है जिसमें किसी भिक्षु ने चीन के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए आत्महत्या कर ली हो। इस घटना से यह साबित होता है कि चीन के शासन से खीजे तिब्बतियों में किस तरह की निराशा और हताशा है।

चीन ने तिब्बत में आए भूकंप पर बनी फिल्म को जब्त किया

एक दर्जन से ज्यादा देशों में रहने वाले हजारों तिब्बतियों ने अपना नया प्रधानमंत्री और निर्वासित संसद चुनने के लिए 20 मार्च को वोट किया। लेकिन चीन के दबाव में आकर नेपाल ने जिस तरह से करीब 20,000 मतदाताओं को मतदान की इजाजत देने से इनकार कर दिया उससे इस चुनाव पर एक बाधा भी आई।

(आरएफए, 31 मार्च)
तिब्बत के क्विंघई प्रांत के युशू क्षेत्र के चीनी अधिकारियों ने एक वृत्त चित्र (डॉक्यूमेंट्री) की सैकड़ों प्रतियां जब्त कर ली हैं जिसमें पिछले साल आए विनाशकारी भूकंप से उबरने में दिखी तिब्बतियों की 'एकता' की तारीफ की गई थी। साल 2010 के अप्रैल माह में चीन के क्विंघई प्रांत के युशु काउंटी में आए जबर्दस्त भूकंप ने तिब्बती कस्बे गेगु को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और इस कस्बे एवं इसके आसपास के इलाकों के करीब 3,000 लोग मारे गए थे। इस वृत्त चित्र का नाम है, "आपदा में आस" (होप इन अ डिजास्टर) और इसका निर्माण बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया है। यह फिल्म तिब्बती लोगों में काफी लोकप्रिय हुई है। लेकिन चीनी अधिकारियों ने जेकुंडो की तीन दुकानों और इसके पास के खम नांगछेन क्षेत्र की दो दुकानों से इस वृत्तचित्र की सैकड़ों डीवीडी जब्त कर ली। इस फिल्म को दिखाने के लिए जेकुंडो के एक रेस्टोरेंट पर जुर्माना भी लगाया गया और रेस्टोरेंट के डीवीडी प्लेयर और प्रोजेक्टर को जब्त कर लिया गया। चीनी अधिकारियों ने एक भिक्षु के आवास से भी इस वृत्तचित्र की 3,000 डीवीडी जब्त कर ली, यही नहीं उनके आवास से एक कंप्यूटर, कई धार्मिक पेंटिंग, घरेलू सामान और 30,000 युआन नकदी भी जब्त कर ली गई। स्थानीय तिब्बतियों का मानना है कि इस वृत्तचित्र को रोकने की वजह यह हो सकती है कि इसमें भूकंप आने के बाद राहत कार्यों के लिए तिब्बत के तीनों परंपरागत प्रांतों के लोगों की एकता की तारीफ की गई है। इसमें यह आह्वान भी किया गया है कि तीनों प्रांतों के लोग भविष्य में आने वाले लक्ष्यों को लेकर एकता बनाए रखें। फिल्म में शामिल एक गीत 'एकता की आवाज़' में कहा गया है कि, 'आम्दो, खम और उ–सांग तीनों एक ही परिवार के अंग हैं। बहुत से तिब्बती यह मानते हैं कि आमदो, खम और उ–सांग से मिलकर ही तिब्बत का निर्माण होता है। हालांकि चीन ने खम और आमदो के बड़े हिस्से को चीनी प्रांतों क्विंघई और सिचुआन में मिला दिया है।

सूत्रों के अनुसार नांगछेन के करीब 400 से 500 तिब्बतियों ने एक याचिका पर दस्तखत कर अधिकारियों से मांग की है कि इस फिल्म का निर्माण करने वाले भिक्षुओं को गिरफ्तार न किया जाए। जेकुंदो और नांगछेन के गांवों के प्रतिनिधियों ने अधिकारियों से मांग की है कि वे इस मसले को 'कायदे से' हल करें नहीं तो हालात बिगड़ने का खतरा बना हुआ है।

चीनी भाासन के खिलाफ तिब्बती भिक्षु ने खुद को जिंदा जलाया

(न्यूयॉर्क टाइम्स, 17 मार्च)

तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ खुद को आग में जला देने वाले युवा तिब्बती भिक्षु का 17 मार्च को निधन हो गया। आधुनिक तिब्बत के इतिहासकारों के अनुसार यह ऐसी पहली घटना है जिसमें किसी भिक्षु ने चीन के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए आत्महत्या कर ली हो। इस घटना से यह साबित होता है कि चीन के शासन से खीजे तिब्बतियों में किस तरह की निराशा और हताशा है। यह भिक्षु 20 साल के फुंसोक, सिचुआन प्रांत के कीर्ति मठ से जुड़े थे। यह मठ चीन की नीतियों के विरोध का केंद्र बन गया है और साल 2008 की जनक्रांति के दौरान यह विशेष रूप से सक्रिय था। न्यूयॉर्क स्थित संगठन स्टूडेंट्स फॉर फ्री टिबेट के कार्यकारी निदेशक तेनजिन दोर्जे ने एक बयान में कहा, "साल 2008 के बाद चीन में लगातार बढ़ रहा चीन का हिंसक शासन ऐसे बिंदु पर पहुंच चुका है, जहां तिब्बती कोई निराशोन्मत कदम उठाने को मजबूर अनुभव कर रहे हैं। फुंसोक जारुतसांग की आत्महत्या इस बात को समझने का एक झरोखा है कि हर जगह के तिब्बती किस तरह की गहरी पीड़ा और कुंठा से गुजर रहे हैं, और यह उनकी सहायता करने का ऐसी आपात जरूरत है जिसको अंतरराष्ट्रीय समुदाय नजरअंदाज नहीं कर सकता। फुंसोक ने गत 16 मार्च को शाम 4 बजे खुद को आग लगा लिया था। वाशिंगटन के संगठन इंटरनेशनल कैम्पेन फॉर टिबेट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके बाद भी चीनी सुरक्षा बलों ने फुंसोक के शरीर में लगी आग को बुझाने की कोशिश के दौरान उन्हें पीटा और लात मारकर धकेल दिया। जब भिक्षु ने खुद को आग लगाई तो उस दौरान और उसके बाद सैकड़ों भिक्षु एवं आम तिब्बती वहां जमा हो गए और इसके बाद सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ही उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और यह विरोध इतना बढ़ गया कि इस महीने यह एक संभावित जनक्रांति का रूप लेने लगा है। फुंसोक के शव को भिक्षु मठ के अंदर ले गए और इसके बाद सुरक्षा बल पूरे कस्बे में तैनात हो गए और

उन्होंने कई स्थानीय लोगों की धरपकड़ की। साल 2008 में तिब्बत की राजधानी ल्हासा में शुरू हुई जनक्रांति को रोकने के लिए कीर्ति मठ में चीनी प्रशासन ने क्रूर कार्रवाई की थी। इस दौरान कीर्ति मठ के आसपास करीब 10 तिब्बतियों को गोली मारी गई थी। भारत के धर्मशाला शहर में रहने वाले भिक्षुओं के पास साल 2008 के विरोध प्रदर्शन के दौरान कीर्ति में गोली से मौत के घाट उतार दिए जाने वाले कई तिब्बतियों की तस्वीरें हैं। इसके पहले फरवरी, 2009 में कीर्ति मठ के ही एक और भिक्षु तापे ने खुद को आग लगा लिया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसकी आग को बुझा दिया जिससे वह बच गए थे। भारत में रहने वाले एक आम तिब्बती थुबटेन गोडुप ने अपनी जन्मभूमि पर चीनी शासन के विरोध में साल 1998 में आत्महत्या कर ली थी। आईसीटी ने यह भी खबर दी है कि गांसू प्रांत में छिपे फिर रहे एक तिब्बती भिक्षु सांगे ग्यात्सो की 26 फरवरी को रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है। वह उन करीब 15 भिक्षुओं में शामिल थे जिन्होंने जियाहे के लाबरांग मठ में अप्रैल, 2008 में विदेशी पत्रकारों के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। इनमें से कम से कम तीन भिक्षु भागकर भारत में शरण ले चुके हैं। इस माह जनक्रांति की संभावना से चिंतित चीनी अधिकारियों ने तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र कहे जाने वाले केंद्रीय तिब्बत में विदेशियों की यात्रा पर रोक लगा दी है। साल 2008 की जनक्रांति के बाद इस क्षेत्र में हर साल मार्च में ऐसी रोक लगाई जाती है।

'प्रतिबंधित' लेखन के लिए चीन ने चार तिब्बतियों को हिरासत में लिया

(नाबा, 6 मार्च)

नाबा प्रशासनिक क्षेत्र के चीनी अधिकारियों ने एक तिब्बती लेखक गेंदुन सेरिंग की दो पुस्तकों में 'प्रतिबंधित' और 'सरकार विरोधी' लेख लिखने के आरोप में चार तिब्बतियों को गिरफ्तार कर लिया है जिनमें दो महिलाएं हैं। गेडुन सेरिंग हाल में ही निर्वासित होकर धर्मशाला आए हैं। गेंदुन एक तिब्बती लेखक और नाबा प्रशासनिक क्षेत्र के ख्युंगछू काउंटी में स्थित रोंगथा मठ के भिक्षु हैं। वह फरवरी 2010 से अपनी गिरफ्तारी से बचते फिर रहे थे और आखिरकार गत फरवरी माह में वह भारत आ गए हैं। रोंगथा मठ के एक और भिक्षु 23 साल के सेरिंग थोंडुप को गेंदुन की किताबों 'टियर्स (आंसू)' और 'लाइव आई' के प्रकाशन में सहयोग देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लाइव आई तिब्बत के भीतर के हालात पर तिब्बती लेखकों द्वारा लिखे गए लेखों का संग्रह है और गेंदुन ने इसका संपादन किया है। लाइव आई में प्रकाशित लेख 'रेतीले तूफान से चीख' लिखने के लिए एक और तिब्बती लेखक सेरिंग तेनजिन को शिनिंग के एक इंटरनेट कैफे से 3 जून, 2011 को गिरफ्तार कर लिया गया। तेनजिन नाबा प्रशासनिक क्षेत्र के जोएग काउंटी के शेरतेंग गांव के रहने वाले हैं और वह पालयुल मठ में भिक्षु हैं। इन दोनों लेखकों को बरखाम काउंटी की जेल में रखा गया है।अधिकारियों ने पंडिता प्रिंटिंग प्रेस के तिब्बती मालिक और दो महिला कर्मचारियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस प्रेस पर ही उक्त किताबें छापने का आरोप है। 17 साल की पेमा सो को 26 फरवरी, 2010 को और 30 साल की यांगछेन की को 30 मार्च, 2010 को गिरफ्तार किया गया। पेमा को बरखाम काउंटी की जेल में रखा गया है, जबकि यांगछेन को नागछू काउंटी की जेल में रखा गया है। हालांकि, बाद में प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को रिहा कर दिया गया।

तिब्बती आंदोलन की अपनी सत्ता चुने हुए प्रतिनिधियों को देने का उनका निर्णय एक अचूक दांव साबित हो सकता है।

चीन ने नेपाल के अपने राजूदत को वापस बुलाया

(हिमालयन टाइम्स, 27 मार्च)

चीन ने नेपाल में अपने राजदूत क्यू गुओहांग को वापस बुला लिया है। एक उच्चस्तरीय सूत्र ने यह जानकारी दी है। क्यू करीब दो साल चार महीने पहले नेपाल में चीनी दूत बनकर आए थे। उनको ऐसे समय में नेपाल से वापस बुलाया गया है, जब उनके तीन साल के सामान्य कार्यकाल में सिर्फ आठ माह बचे थे। सूत्रों के अनुसार राजदूत क्यू ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी नेपाल के विदेश सचिव डॉ. मदन कुमार भट्टाराई को दे दी है। सूत्रों के अनुसार चीन का विदेश मंत्रालय नेपाल में चीन विरोधी गतिविधियों पर विराम लगाने के बारे में उनकी कमजोर कूटनीति से असंतुष्ट था। क्यू के साल 2008 में नेपाल आने के बाद से ही नेपाल में तिब्बत की आज़ादी की मांग करने जैसी कई गतिविधियां जारी रही हैं, जो चीन की सबसे बड़ी चिंता है। चीनी दूतावास के एक अधिकारी ने भी इस बात की पुष्टि की है। हालांकि उसने और कोई जानकारी नहीं दी। क्यू के दो हफ्ते के भीतर बीजिंग लौटने की उम्मीद है।

"यह चुनाव नेपाल की विदेश नीति को प्रभावित करता है और यह एक पड़ोसी देश के हितों के खिलाफ होगा, इसलिए इसकी निश्चित रूप से इजाजत नहीं दी जा सकती।"

चीनी प्रतिबंध की वजह से तिब्बती वेबसाइट को बंद करना पड़ा

(कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स, 23 मार्च)

कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (सीपीजे) ने मांग की है कि चीनी अधिकारियों को इस बात की इजाजत देनी चाहिए कि बिना किसी वजह के बंद कर दिए जाने वाले तिब्बती समाचार और ब्लॉग साइट को फिर से चलाया जा सके। तिब्बती मामलों पर चीनी भाषा

भारत की मौजूदा युद्ध सिद्धांत इस संभावना पर विचार करता है कि पाकिस्तान और चीन के दोहरे मोर्चे से लड़ाई करनी पड़ सकती है, इसलिए सामरिक योजना भी कई जमीनी सचाइयों के आधार पर तैयार की जाती है।

में चलाई जा रही वेबसाइट *तिब्बतकुल* के संस्थापकों में से एक वांगचुक सेतेन ने अपने व्यक्गित ब्लॉग में लिखा है कि लंदन के तिब्बती आंदोलनकारी और ब्लॉगर डेछेन पेम्बा के *ग्लोबल वायसेज ऑनलाइन* पर लिखे लेख के अनुवाद के अनुसार उक्त वेबसाइट 16 मार्च से बंद हो गया है। वांगचुक सेतेन ने लिखा है, "उच्चाधिकारियों ने कई सर्वर ऑपरेटर को इस साइट को बंद करने का आदेश दिया है लेकिन यह निर्णय क्यों लिया गया इसकी जानकारी गोपनीय रखी गई है। इसके कुछ दिनों पहले ही दस मार्च को इससे जुड़ी एक और वेबसाइट *'मायबुडाला'* को भी बंद कर दिया गया। *मायबुडाला* में एक सोशल नेटवर्किंग का भी खंड था, लेकिन वह भी नहीं खुल रहा है। डेछेन पेम्बा ने सीपीजे को ई–मेल से बताया कि दो और तिब्बती भाषा के वेबसाइट *डोबुमनेट* और *संगधोर* को भी बंद कर दिया गया है। कई ब्लॉगरों द्वारा चीन में सरकार विरोधी 'जास्मीन क्रांति' के आह्वान के बाद चीन में हाल के दिनों में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों पर निगरानी, पकड़–धकड़ और सेंसरशिप बढ़ गई है। जास्मीन क्रांति मध्य–पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी देशों की तर्ज पर चलाया जा रहा आंदोलन है। सीपीजे के एशिया समन्वयक बॉब डिएट्ज ने बताया, "इंटरनेट की दुनिया से यदि कुछ और तिब्बती आवाज़ गायब हो जाएं तो चीन के लिए यह कोई अचरज की बात नहीं होगी, लेकिन यह हम सबको परेशान करने वाली बात है। नस्लीय अल्पसंख्यक, आंदोलनकारी और सरकार विरोधी राय पर चीनी अधिकारियों के सूचनाओं के दमन के नवीनतम प्रयास के तहत लगातार उत्पीड़न बढ़ रहा है।"

डेछेन पेम्बा ने सीपीजे को ई–मेल से बताया है, "यह वास्तव में परेशान करने वाली बात है कि *तिब्बतकुल* को अचानक बंद कर दिया गया। इस पर सात साल की सामग्री थी और इसके करीब 80,000 रजिस्टर्ड यूजर थे।

निर्वासित तिब्बतियों ने नए नेताओं के लिए वोट किया

"इतिहास का तानाशाह : चीन के संकट की जड़"।

(आरएफए, 20 मार्च)

एक दर्जन से ज्यादा देशों में रहने वाले हजारों तिब्बतियों ने अपना नया प्रधानमंत्री और निर्वासित संसद चुनने के लिए 20 मार्च को वोट किया। लेकिन चीन के दबाव में आकर नेपाल ने जिस तरह से करीब 20,000 मतदाताओं को मतदान की इजाजत देने से इनकार कर दिया उससे इस चुनाव पर एक बाधा भी आई।

दक्षिण भारत, उत्तर अमेरिका, यूरोप, जापान, ताईवान और आस्ट्रेलिया में रहने वाले 83,000 से ज्यादा तिब्बतियों ने धर्मशाला स्थित अपनी निर्वासित सरकार के संसद सदस्यों और कालोन ट्रिपा यानी प्रधानमंत्री का चुनाव किया।

नेपाल में निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रतिनिधि थिनले ग्यात्सो ने बताया कि नेपाल के उच्चाधिकारियों ने उनसे कहा, "यह चुनाव नेपाल की विदेश नीति को प्रभावित करता है और यह एक पड़ोसी देश के हितों के खिलाफ होगा, इसलिए इसकी निश्चित रूप से इजाजत नहीं दी जा सकती।"

पिछले साल नेपाल की राजधानी काठमांडू में जब कालोन ट्रिपा के चुनावों के प्रारंभिक दौर चल रहे थे तो दंगा नियंत्रक उपायों से लैस पुलिस ने काठमांडू के तीन मतदान केंद्रों पर धावा बोल दिया और वे मतदान पेटी को उठाकर ले गए।

वाशिंगटन के संगठन इंटरनेशनल कैंपेन फॉर टिबेट (आईसीटी) ने कहा, "समूचे तिब्बती प्रवासी जगत में आशावाद का जो माहौल बना था, वह इस समाचार से खराब हो गया कि नेपाल में रहने वाले तिब्बतियों को काठमांडू के नेपाली प्रशासन ने मतदान का अधिकार नहीं दिया।

सत्ता छोड़ने का दलाई लामा का निर्णय सही दिशा दिखाता है

(द पायोनियर, 18 मार्च)

प्रेमेन रेड्डी

दुनिया भर में अपने समुदाय एवं लोगों के बीच सम्मानित दलाई लामा में ईश्वरत्व और महानता का एक दुर्लभ संगम है जिस पर बुद्धिमत्ता और विनोद की चांदनी बिखरी हुई है और जिससे उनके चीनी विरोधी भी चकरा जाते हैं। तिब्बती आंदोलन की अपनी सत्ता चुने हुए प्रतिनिधियों को देने का उनका निर्णय एक अचूक दांव साबित हो सकता है। सत्ता और अधिकार को संस्थागत रूप देकर और अपने सांसारिक पहलुओं को आध्यात्मिक पहलू से अलग कर उन्होंने तिब्बती जनता और उनके आंदोलन को ऊंची उड़ान दी है, जिससे उन्हें देशों के शिष्टाचार में एक विशिष्ट स्थान हासिल हो सकता है। चीन के पास अब धार्मिक नेता पर हमले के लिए कुछ नहीं बचा है, उनके इस कदम ने चीनी शासन के खोखलेपन को उजागर कर दिया है।

बीजिंग ने प्रस्ताव रखा है कि भविष्य में दलाई लामा की नियुक्ति एक ऐसी प्रक्रिया से होगी जो चीन के मांचू शासकों द्वारा तय की गई थी। दलाई लामा के दावेदारों का नाम अलग–अलग कागज पर लिखा जाएगा और इन सबको एक बर्तन में रखा जाएगा जिसके बाद ड्रा निकाला जाएगा। इस प्रकार राजनीति एक लॉटरी तक सीमित हो जाएगी, 21वीं सदी के

जमाने में 18वीं सदी का अवशेष बनाए रखने की यह कोशिश है। इसलिए कोई अचरज की बात नहीं कि इतिहासकार डब्ल्यूएफ जेनर की प्रारंभिक पुस्तक का शीर्षक है, "इतिहास का तानाशाह : चीन के संकट की जड़"। इस देश का मरा हुआ वर्गवाद, करीब दो हजार साल के केंद्रीय शासन के दम पर टिका हुआ है और जिसे इसके आधुनिक शासक भी सहन कर रहे हैं। जेनर बताते हैं, "गैर हॉन को आज़ादी इस शर्त पर ही है कि वे खुद को हान परंपरा को अपनाने के लिए राजी कर लें। कागजी तौर पर तो उनके नाम को चीनी फॉर्म और चीनी अक्षरों में लिखकर आसानी से पूरे समाज में समावेशित करने की बात की जा सकती है, लेकिन सचाई ऐसी नहीं है। इस बात की कल्पना कर पाना बेहद कठिन है कि चीन में ऐसी कोई इतिहास की पुस्तक प्रकाशित हुई हो जिसमें हान चीनियों के विस्तारवाद को नस्ली संहार बताया गया हो। चीन में जैसा इतिहास लिखा गया है उससे यह मानने में भी मुश्किल होती है कि कई चीनी शासकों के समय बड़ी संख्या में ऐसे शासक रहे जिन्होंने चीन की केंद्रीय सत्ता का अपने ऊपर प्रभुत्व या अपने क्षेत्र के ऊपर चीनी शासन को मानने से इंकार किया था। यही चीन–तिब्बत रिश्ते की भी पृष्ठिभूमि है और इसी से भारत–चीन रिश्ते में मौजूदा चुनौतियां भी पैदा हुई हैं।

तिब्बत के ऊपर अपना पुराना अधिकार जताने की मांचू चीन की दृढ़ता, यहां तक कि राजवंश के पतन के दिनों में भी, हाल के समय का एक सबक है। वाशिंगटन डीसी में तैनात ब्रिटिश राजदूत लॉर्ड ब्राइस ने जब राष्ट्रपति थियोडारे रूजवेल्ट से हासिल अमेरिका के यात्रा प्रेमी और तिब्बत मामलों के जानकार डब्ल्यूडब्ल्यू रॉकहिल की एक गोपनीय रिपोर्ट पढ़ी तो उन्होंने लिखा–"वहां के प्रति एक प्रकार की दुःखद रुचि है। यह देखकर कि किस प्रकार चीन सरकार एक बड़े एनाकोंडा सांप की तरह भाग्यहीन दलाई लामा को अपने कुंडली में लपेट लिया है और उनको तब तक दबाने की कोशिश कर रहा है जब तक कि उनका पूरी तरह खात्मा न हो जाए।" साल 1906 में जब चीनी सेनाओं के दस्ते तिब्बत की राजधानी ल्हासा में मार्च कर रहे थे तब 13वें दलाई लामा को भारत की शरण लेनी पड़ी थी। इस दौरान तिब्बती मठों को बड़े पैमाने पर लूटा गया और उनके बेशकीमती एवं पवित्र खाका से हमलावर सैनिकों ने अपने जूते चमकाए। मांचू राजवंश के पतन के बाद और प्रथम विश्वयुद्ध की शुरुआत के पहले ब्रिटिश, चीनी और तिब्बती वार्ताकार शिमला में इस बात पर वार्ता करने के लिए जुटे कि तिब्बत की स्थिति आगे क्या होगी। इस वार्ता के अंत में 3 जुलाई, 1914 को एक बकवास शिमला समझौता हुआ। इस समझौते से कुछ भी सुलझ नहीं पाया। ब्रिटिश कूटनीतिक वाकछल की इस कवायद में तिब्बत को माओत्से तुंग के गिरोह के हाथों में सौपने की भूमिका पचास साल पहले ही तैयार कर ली गई।

दिसंबर, 1950 में सरदार वल्लभभाई पटेल ने चेतावनी दी थी, "चीनी साम्यवादी साम्राज्यवाद में छुपे हुए नस्लीय, राष्ट्रीय और ऐतिहासिक दावे हैं। हमारे पश्चिमी और उत्तर–पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा के लिए खतरा पहले जैसा ही बना हुआ है, अब उत्तर और उत्तर–पूर्व की तरफ से नया खतरा पैदा हुआ है। भारत के रक्षा तैयारी को एक साथ दो मोर्चे पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमारी अभी तक की रक्षा तैयारी इस अनुमान पर आधारित है कि हम पाकिस्तान से बेहतर हैं।"

भारत की मौजूदा युद्ध सिद्धांत इस संभावना पर विचार करता है कि पाकिस्तान और चीन के दोहरे मोर्चे से लड़ाई करनी पड़ सकती है, इसलिए सामरिक योजना भी कई जमीनी सचाइयों के आधार पर तैयार की जाती है। बंटवारे के सर्जरी के बाद 1950 में भारत एक कमजोर स्थिति में आ गया था। लेकिन आज स्थिति काफी अलग है। लेकिन इस बात को भी सभी स्वीकार करते हैं कि हिमालय अब भारत के लिए वैसा लौह सुरक्षा कवच नहीं बन सकता जैसा कि 1940 में फ्रांस के लिए मैगिनोट लाइन था।

14वें दलाई लामा का 1959 में भागकर भारत आना और भारत सरकार द्वारा उन्हें और उनके अनुयायियों को शरण देने को चीन ने अपने अपमान के तौर पर लिया। चीन की स्वयं की बनाई इस धारणा को कुछ वजहों से नकार पाना कठिन है कि यह मध्यवर्ती देश एशिया का अकेला और वास्तविक महान ताकत है। आखिरकार हम एक पापी तानाशाह का सामना कर रहे हैं।

भारतीय रक्षा मंत्रालय के साल 2010–11 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने अपनी सामरिक योजना में चीन की सैन्य क्षमताओं को भी जोड़ा है। रक्षा मंत्रालय की इस रिपोर्ट के अनुसार चीन की लगातार बढ़ती क्षमता पर भारत ने अपनी दृष्टि और पैनी कर ली है।

चीन ने तिब्बत में हवाई अड्डों और रेल–सड़क संपर्क का जाल बिछाया

(टाइम्स ऑफ इंडिया, 8 मार्च)

तिब्बत के क्विंघई इलाके में परमाणु मिसाइल बेस बनाने के अलावा (जिसका निशाना निश्चित रूप से भारत है) चीन ने तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में पांच पूरी तरह चालू हवाई अड्डे, गहन रेल नेटवर्क और करीब 58,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछा दिया है। पांच हवाई अड्डों के अलावा चीन की जनमुक्ति सेना टीएआर और दक्षिणी चीन में कई हवाई पट्टियों को उन्नत बना रही है। उक्त पांच हवाई अड्डों से हाल के दिनों में चीनी सुखोई–27यूबीके और सुखोई 30एमकेके लड़ाकू विमानों का अभ्यास

वे अरुणाचल प्रदेश के लोगों को नत्थी वीजा दे रहे हैं।

(1)

(2)

(10)

कैमरे की आंख

1. साल 2010 में धर्मशाला में एक प्रार्थना समारोह के दौरान परमपावन दलाई लामा (फाइल
2. 'बर्फीला चुनाव': लद्दाख के झांगथांग क्षेत्र में स्थित छुमुर (समुद्र तल से 18,000 फुट ऊपर) में
के लिए खच्चर पर मतदान पेटी रखकर साथ चलते हुए एक मतदान कर्मचारी। इस चुनाव
चढ़ाई कर मतदान स्थल तक पहुंचे।
3. तिब्बती जनक्रांति दिवस की 52वीं वर्षगांठ के अवसर पर इटली के शहर रोम में चीनी दूतावा
4. निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री पद के दावेदार लोबसांग सांगे भारत के मैक्ल्योडगंज
अधिकारियों को अपना पहचान पत्र दिखाते हुए।
5. चीन के भीतर रहने वाले लोगों की जी–मेल तक पहुंच बाधित कर दी गई है और कई विदेशी
फोटोः रायटर्स
6. भारत के धर्मशाला में 14 मार्च, 2011 सोमवार से निर्वासित तिब्बती संसद का 10 दिन तक चल
द्वारा अपने राजनीतिक अधिकार चुने हुए नेता को देने के निर्णय पर चर्चा करेंगे।
7. तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ हुई साल 1959 की जनक्रांति की वर्षगांठ के अवसर पर
से पीटती नेपाल की दंगा पुलिस। करीब 1,000 निर्वासित तिब्बती अपने जन्मभूमि पर चीनी
नेपाली पुलिस ने धावा बोल दिया। (एपी फोटो–बिनोद जोशी)
8. तिब्बती युवाओं ने रविवार, 20 मार्च, 2011 को धर्मशाला स्थित मतदान केंद्र पर अंतिम दौर के
9. जापान में 11 मार्च शुक्रवार को भीषण भूकंप के बाद सुनामी का प्रकोप हुआ। जापान के एनएच
में जहाज और नावें बहकर तटों पर आ गईं दिख रही हैं। (एपी फोटो/एनएचके टीवी)
10. धर्मशाला के मुख्य मंदिर में रविवार 13 मार्च, 2011 को जापान के सुनामी पीड़ितों के लिए दि

(9)

(8)

आंखों देखी

(3)

(4)

(5)

ेमरे की आंख से

ई लामा (फाइल फोटो) ।

3,000 फुट ऊपर) में 20 मार्च, 2011 को कालोन ट्रिपा (प्रधानमंत्री) और सांसदों के तिब्बतियों के चुनाव
र्मचारी। इस चुनाव के लिए –45 डिग्री सेल्सियस तापमान के बावजूद मतदाता करीब 12 घंटे तक

रोम में चीनी दूतावास के सामने मौजूद इटली के तिब्बत समर्थक।
रत के मैक्ल्योडगंज शहर में 20 मार्च, 2011 को चुनाव के दौरान अपना वोट डालने के लिए चुनाव

है और कई विदेशी पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि उनके मेल एकाउंट को हैक किया जा रहा है।

का 10 दिन तक चलने वाला बजट सत्र शुरू हुआ। इस सत्र के दौरान तिब्बती सांसद दलाई लामा
करेंगे।
गांठ के अवसर पर नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शन कर रहे निर्वासित तिब्बतियों को लाठियों
जन्मभूमि पर चीनी शासन के खात्मे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन पर

द्र पर अंतिम दौर के चुनावों के लिए वोट डाले।
। जापान के एनएचके टीवी द्वारा ली गई इस वीडियो तस्वीर में अओमोरी प्रशासनिक क्षेत्र के हैशिन्हो
नएचके टीवी)
पीड़ितों के लिए दिन भर के एक विशेष प्रार्थना सभा की अध्यक्षता करते नामग्याल मठ के प्रमुख।

(फोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में)

(7)

(6)

रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक भारत की इस वृहद और महत्वाकांक्षी योजना के तहत पहले चरण में भारतीय सीमा सड़क संगठन की तरफ से 227 सड़कों को विकसित किया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 13,100 किलोमीटर होगी।

देखा गया है। इसके अलावा टीएआर में गहन सड़क–रेल संपर्क मार्ग की वजह से अब जनमुक्ति सेना सिर्फ 20 दिनों के अंदर भारतीय सीमा पर स्थित अपने लॉन्च पैड पर दो डिवीजन (30,000 सैनिकों) तैनात कर सकती है, जबकि पहले इसमें 90 दिन लगते थे। यह सब कोई नए समाचार नहीं हैं, लेकिन चीन द्वारा अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 91.5 अरब डॉलर कर देने के बाद 7 मार्च को लोकसभा में चीन द्वारा भारी सैन्य ढांचा तैयार करने पर चिंता देखी गई। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर 19 सांसदों ने रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी से सवाल किया कि क्या यूपीए सरकार ने करीब 4,057 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 'बढ़ती चीनी सेना की गतिविधियों का संज्ञान लिया है।' इसके जवाब में एंटोनी ने कहा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के अनुरूप सभी 'जरूरी कदम' उठाए गए हैं। उन्होंने कहा, "सैन्य क्षमता वृद्धि और सेनाओं का आधुनिकीकरण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और यह देश के सामने आने वाली चुनौतियों के अनुरूप होता है। तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में साल 2010 में कुल 58,000 किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क का आकलन किया गया है। क्विंघई–तिब्बत रेलवे का विस्तार शिगास्ते तक किया जा रहा है। सीक्यांग में कशगर से होतम तक एक और रेलमार्ग का विस्तार हो रहा है। टीएआर के गोंगार, पांगता, लिंछी, होपिंग और गार गुंसा में पांच नए हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं।"

भारत अब देर से ही सही, पर चीन के मुकाबले सामरिक रूप से तैयार रहने की कोशिश कर रहा है। पिछले सप्ताह ही दो नए सुखोई–30 एमकेआई विमानों ने असम के छाबुआ एयरबेस पर पहुंचे हैं। यह उत्तर–पूर्व में तेजपुर के बाद बहुपक्षीय भूमिका वाले लड़ाकू विमानों का दूसरा एयरबेस है। इन दोनों एयरबेस पर दो सुखाई स्क्वाड्रन (प्रत्येक में 16 से 18 जेट विमान) हैं।

भारत को चीन और घुसैपठियों से खतराः राजनाथ

जिसके तहत पांगसाउ दर्रे तक इस ऐतिहासिक सड़क को उन्नत किया जाना है।

(पीटीआई, 21 मार्च)

वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह का कहना है कि भारत की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा पर भारी खतरा है क्योंकि एक तरफ चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा कर रहा है और दूसरी तरफ घुसपैठिए देश के भीतर समस्याएं पैदा कर रहे हैं। भाजपा की एक बैठक को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, "चीन यह दावा कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है, जबकि यह भारत का हिस्सा है। वे अरुणाचल प्रदेश के लोगों को नत्थी वीजा दे रहे हैं। इसलिए भारत को भी चीन को यह बता देना चाहिए कि वह तिब्बत से आने वाले लोगों को नत्थी वीजा देगा। लेकिन भारत सरकार में फिलहाल ऐसा करने का साहस नहीं दिख रहा है।" कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को कमजोर बताते और ब्रह्मपुत्र की धारा मोड़ने के चीनी प्रयास का विरोध न करने के लिए विदेश मंत्री की आलोचना करते हुए राजनाथ ने कहा, "सत्ता में आने पर भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मपुत्र की धारा मोड़े जाने के खिलाफ राजनयिक दबाव बनाएगी और एक अंतरराष्ट्रीय जल समझौता करेगी।

भारत ने चीनी सेना की क्षमता का आकलन किया

(यूपीआई, 21 मार्च)

भारतीय रक्षा मंत्रालय के साल 2010–11 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने अपनी सामरिक योजना में चीन की सैन्य क्षमताओं को भी जोड़ा है। रक्षा मंत्रालय की इस रिपोर्ट के अनुसार चीन की लगातार बढ़ती क्षमता पर भारत ने अपनी दृष्टि और पैनी कर ली है।

न्यूज इंटरनेशन में सोमवार को प्रकाशित खबर के अनुसार इस रिपोर्ट में कहा गया है, "भारत सचेत है और हम लगातार तात्कालिक और पड़ोसी के वृहद रिश्ते के संदर्भ में चीन की बढ़ती सैन्य क्षमता के निहितार्थों पर नजर रखे हुए हैं।" इस रिपोर्ट से मिले–जुले संकेत मिलते हैं। रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत–चीन के संबंध 'गंभीर महत्व' के हैं और चीन के साथ संवाद रखने की भारत सरकार की नीति 'परस्पर भरोसे, सम्मान और एक–दूसरे की संवदेनशीलता के सिद्धांतों पर आधारित है।' दूसरी तरफ रिपोर्ट में यह भी साफ किया गया है कि भारत के मुकाबले तैयार की जा रही चीनी सैन्य क्षमता भविष्य में नई दिल्ली के लिए चिंता का विषय हो सकती है। खासकर, जम्मू–कश्मीर के अनसुलझे मसले के कारण भारत के लोग पाकिस्तान को अपना मुख्य शत्रु मानते हैं, लेकिन चीन की बढ़ती सैन्य ताकत ने भारत के रक्षा अधिकारियों का ध्यान इस संभावित खतरे की ओर केंद्रित किया है। भारत के सामरिक हितों को व्यापक करने की रणनीतिक पाकिस्तान से हटने के ऐतिहासिक बदलाव को प्रदर्शित करता है। चीन अब भारत के लिए एक बढ़ता प्रतिस्पर्धी है जिसके साथ वह विवादास्पद उत्तर–पूर्वी हिमालयी सीमा क्षेत्र में 1962 में एक युद्ध भी कर चुका है।

भारत के तेजी से बढ़ते रक्षा बजट की वजह से यह अपने पर्वतीय सैन्य डिवीजनों को मजबूत बनाने में सक्षम हुआ है और अंतरराष्ट्रीय बाजार से ऐसे विशेष

हथियार खरीदने में सक्षम हुआ है जिससे चीन के साथ संभावित पर्वतीय युद्धों में आसानी हो।

कश्मीर पर चीन के बयान से भारत कुपित
(द डिप्लोमेट, 25 मार्च)
राजीव शर्मा
कश्मीर को लेकर चीन के ताज़ा बयान से भारत की भौहें तन गई हैं। पाकिस्तान में चीन के राजदूत लीयू जियान ने अपने एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए चीन के नत्थी वीजा की नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। लीयू जियान की तरफ से हाल ही में दिए गए इस बयान के बाद हालांकि भारत की तरफ से ज्यादा हंगामा नहीं किया गया है। लीयू जियान ने ये विवादित बात "इवाल्विंग ग्लोबल एंड रिजनल सीनारियो" विषय पर आयोजितएक सेमिनार के दौरान कही थीं। लीयू ने इस दौरान कहा कि कश्मीर को लेकर चीन की स्टेपल्ड वीजा नीति जारी रहेगी, इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। सार्वजनिक तौर पर इस विवादित नीति की पुष्टि करने से भारत की नाराजगी काफी बढ़ गई है। क्योंकि यह चीन की तरफ से इस नीति के कठोर बने रहने की ओर इशारा करता है, जो दोनों देशों के बीच एक संवेदनशील मुद्दा बना रहा है।
पाकिस्तान की धरती पर पाकिस्तान में चीन के राजदूत का दिया गया यह बयान भारत के लिए खास मायने रखता है। चीन सार्वजनिक तौर पर कश्मीर को मुद्दा बनाता रहा है और स्पष्ट करता रहा है कि वह इस मुद्दे पर किसे समर्थन करता है। लीयू का यह बयान निश्चित तौर पर पाकिस्तान को खुश करने वाला है। दूसरी तरफ, भारत भी कि चीन के साथ होने वाली किसी भी डील को लेकर अपने इरादे जाहिर कर चुका है। उदाहरण के तौर पर, चीनी राष्ट्रपति वेन जियाबाओ की होने वाली भारत यात्रा के बावजूद भारत ने चीन के उस अनुरोध को नजरंदाज कर दिया, जिसमें चीन ने भारत से नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में हिस्सा नहीं लेने का अनुरोध किया था। यही नहीं वेन की यात्रा के दौरान भारत बराबर चीन को यह संदेश देता रहा कि कश्मीर मुद्दा उसके लिए उतना ही संवेदनशील है जितना कि चीन के लिए तिब्बत। चीन के इस नए कदम के बाद भारत तिब्बत और ताइवान के मुद्दे पर अपना रुख कड़ा कर सकता है।

पाक–चीन सीमा पर भारत की 558 सड़क परियोजनाएं प्रस्तावित
(आईएएनएस, 28 मार्च)
सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए भारत ने 27,986 किलोमीटर सड़क बनाने का फैसला किया है। इसके तहत 500 अरब रुपए की लागत से करीब 558 सड़क परियोजनाएं प्रस्तावित की गई है। इसे 2030 तक पूरा किया जाना है। भारत के इस प्रस्तावित सड़क परियोजना का मकसद पाकिस्तान–चीन से लगते सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचनाओं का मजबूत करना है ताकि सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ाई जा सके। दो चरणों में पूरा होने वाली इस परियोजना को चीन द्वारा तिब्बत में पिछले एक दशक से किए जा रहे बुनियादी विकास और पाकिस्तान की तरफ से विकसित की गई 5 बड़ी सड़क परियोजनाओं का जवाब माना जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक भारत की इस वृहद और महत्वाकांक्षी योजना के तहत पहले चरण में भारतीय सीमा सड़क संगठन की तरफ से 227 सड़कों को विकसित किया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 13,100 किलोमीटर होगी। इस पर करीब 248.86 अरब रुपए की लागत आएगी। जबकि दूसरे चरण में कुल 281 सड़कें बनाई जाएंगी। जिसकी कुल लंबाई होगी 14,886 किलोमीटर और लागत होगी 252.68 अरब रुपए होगी।
हालांकि पहले चरण के निर्माण के लिए 2012 की समय सीमा तय की गई थी। लेकिन निर्माण कार्यों में लक्षित गति नहीं आ पाने की वजह से इसे बढ़ाकर साल 2015 तक कर दिया गया है। इसी तरह दूसरे चरण के 2022 तक पूरी होने की उम्मीद थी, लेकिन इसे भी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक चीन–भारत सीमा से लगते 73 सड़कों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए जम्मू–कश्मीर में बीआरओ की 61 इकाइयां, हिमाचल प्रदेश में 7 इकाइयां, उत्तराखंड में 33 इकाइयां, अरुणाचल प्रदेश के लिए 46 इकाइयां और सिक्किम के लिए 21 इकाइयों को भेजा गया है, ताकि तय समय सीमा में काम पूरा हो सके।

'हमारे हिसाब से हमें उत्तर और उत्तर पूर्व में साम्यवादी चीन का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। साम्यवादी चीन की अपनी एक निश्चित महत्वाकांक्षा और लक्ष्य है, जो किसी भी सूरत में हमारे लिए मित्रवत नहीं है। इन सबका उल्लेख पत्र में किया गया था।''

स्टिलवेल मार्ग को उन्नत करने की कोशिश कर रहा है चीन

(असम ट्रिब्यून, 27 मार्च)
भारत की तरफ से भले ही ऐतिहासिक स्टिलवेल रोड के दुबारा खोले जाने की परियोजना का करीब करीब पटाक्षेप हो गया हो, लेकिन चीन अब भी इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर खास उत्साहित नजर आ रहा है। असम के लेडो से 61 किलोमीटर की दूरी से गुजरती इस 1,031 किलमीटर लंबी सड़क के विकास के लिए चीन ने तो बकायदा निविदाएं भी निकाल दी है। जिसके तहत पांगसाउ दर्रे तक इस ऐतिहासिक सड़क को उन्नत किया जाना है।

भारत सरकार ने स्टिलवेल रोड को नहीं खोलने का निर्णय लिया था।

जब उन जगहों पर भारतीय सेनाओं ने हमला किया तो उन्हें चीनी हथियार और चीन के साथ उनके संबंध बताने वाले कुछ कागजात भी मिले।

रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में चीन के इस परियोजना का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चीन अपने सभी राजमार्गों, व्यापारिक केंद्रों और बड़े सैन्य इकाइयों को सभी दर्रों, वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा एवं सेना के बेस कैंपों को जोड़ने के लिए सड़कों का निमार्ण कर रहा है। रक्षा मंत्रालय की इस रिपोर्ट जारी होते ही एक संसदीय समिति ने मंत्रालय के आत्मसंतुष्ट रहने और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, खासकर चीन में हो रही गतिविधियों से जुड़े विस्तष्त आंकड़े नहीं जुटाने की आदत पर कड़ी फटकार लगाई। म्यांमार सीमा पर चीन की गतिविधियों और स्टिलवेल रोड के निमार्ण की जानकारी रक्षा मंत्रालय की एक संसदीय समिति को दी गई थी। 1739 किलोमीटर लंबा स्टिलवेल रोड असम से शुरू हो कर भारत–म्यांमार सीमा पर मौजूद पांगसाउ दर्रे से होते हुए दक्षिणी चीन के युन्नान प्रांत के कुंमिंग को जोड़ता है।

इस ऐतिहासिक सड़क के विकास की परियोजना को चीन ने मई 2007 में ही शुरू कर दिया था। शुरुआती दौर में, चीन ने कुंमिंग–म्यीतक्यीना के बीच कंबैती दर्रे से गुजरती 647 किलोमीटर लंबी सड़क को उन्नत किया था। भारत सरकार ने स्टिलवेल रोड को नहीं खोलने का निर्णय लिया था। रक्षा मंत्रालय ने सरकार के इस निर्णय से संसद की स्थायी समिति को अवगत करा दिया था।

देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है भानुपल्ली–लेह लाइन

नवंबर 1966 में चीन ने 300 नगा विद्रोहियों के एक दल को अपने यहां आंदोलन के लिए हथियार उपलब्ध कराने के साथ प्रशिक्षित भी किया।

(टाइम्स ऑफ इंडिया, 29 मार्च) हिमाचल के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माने जाने वाले भानुपल्ली– बिलासपुर– मनाली–लेह रेल लाइन को लेकर कई बार केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि धूमल ने ही पहली बार इस महत्वपूर्ण लाइन को लेकर केंद्र सरकार से दरख्वास्त की है। इससे काफी पहले 7 नवंबर, 1950 को स्वतंत्र भारत के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु को लिखे गए एक पत्र में इस लाइन का उल्लेख किया था। संचार तंत्र को मजबूत करने संबंधी विषय पर लिखे गए इस पत्र में उन्होंने इस लाइन के विकास पर जोर दिया था। यह पत्र उन्होंने तिब्बत पर चीन के कब्जा किए जाने के तुरंत बाद लिखा था।

भाजपा के पूर्व प्रवक्ता अशोक कपाठिया के मुताबिक धूमल अपने इस विचार के जरिए केंद्र तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि लेह तक प्रस्तावित लाइन का निमार्ण अति शीघ्र हो। अशोक कपाठिया ने धूमल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पटेल का अंदेशा उस वक्त पूरी तरह सच साबित हुआ था जब 1962 में भारत–चीन और उसके बाद करगिल युद्ध का सामना देश को करना पड़ा।

अशोक कपाठिया बताते हैं कि पटेल ने अपने पत्र में लिखा था कि अग्रिम मोर्चे पर देश के रेल, वायु, सड़क, वायरलेस और संचार तंत्र के विकास को पूरी प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। पटेल के पत्र का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, ''हमारे हिसाब से हमें उत्तर और उत्तर पूर्व में साम्यवादी चीन का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। साम्यवादी चीन की अपनी एक निश्चित महत्वाकांक्षा और लक्ष्य है, जो किसी भी सूरत में हमारे लिए मित्रवत नहीं है। इन सबका उल्लेख पत्र में किया गया था।'' कपाठिया कहते हैं कि पटेल ने बिना लाग लपेट के अपने पत्र में लिखा था, "तिब्बत का अस्तित्व खत्म हो गया जैसा कि हम सभी जानते हैं और चीन हमारे दरवाजे तक पहुंच गया है, इसलिए हमें इस नए हालात पर सोचना होगा।" उन्होंने कहा कि अगर इतिहास देखें तो, उत्तर–पूर्वी हिस्सा हमारे लिए कभी भी चिंता की वजह नहीं रहा है, क्योंकि उत्तर से दुश्मनों के खिलाफ हिमालय हमेशा से एक अभेद्य दीवार रहा है।

क्या चीन भारतीय विद्रोही संगठनों को समर्थन दे रहा है?

(द डिप्लोमैट, 22 मार्च)

25 जनवरी 2011 को एक टीवी रिपोर्टर के रूप में काम कर रही वेंग किंग नाम की एक चीनी जासूस को नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम (इसाक–मुइवा), जो कि भारत का सबसे बड़ा विद्रोही ग्रुप है, के साथ गुप्त बैठक करने के जुर्म में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा गिरफ्तार किया गया। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि वेंग किंग ने स्वीकार किया है वह चीनी इंटेलिजेंस ब्यूरो (पीपुल्स सिक्योरिटी ब्यूरो) की सदस्य है। उसने एनएससीएन–आईएम के विद्रोही नेता थूंगुलेंग के साथ बंद कमरे में चार घंटे तक बैठक की। यह भी बताते चलें कि थूंगुलेंग इन दिनों भारत सरकार के साथ बातचीत भी कर रहा है। हालांकि इस विद्रोही ग्रुप ने कहा है, "हम भारत सरकार के साथ सकारात्मक भावना के साथ बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा चीन से कोई नाता नहीं है।" जबकि उत्तर–पूर्व भारत में चल रही उथल–पुथल में इस विद्रोही ग्रुप और चीनी इंटेलिजेंस एजेंसी की भूमिका जगजाहिर है। यह भारत के दृष्टिकोण से चिंता का विषय है क्योंकि किंग का मामला तो एकमात्र बानगी भर है। चीन, भारत के साथ लगने वाले अपने संवेदनशील सीमाओं में विस्तार

के लिए भारतीय क्षेत्र को अपना कहता रहा है और उसपर दबाव बनाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाता रहा है। शांति प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने के लिए चीन इस तरह के प्रयास कर रहा है। *आउटलुक* पत्रिका द्वारा किये गए एक खुलासे मे यह बात निकल कर सामने आई की भारत सरकार द्वारा जारी एक 100 पन्नों के रिपोर्ट में इस तरह की घटनाओं का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में अक्टूबर 2010 में एनएससीएन–आईएम के एक सदस्य एंथनी शिमरे की भारतीय अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी की बात का भी जिक्र है, जो बैंकॉक से ग्रुप का संचालन कर रहा था। भारतीय अधिकारियों द्वारा किये गए पूछताछ में उसने बताया कि उसके ग्रुप को चीनी इंटेलिजेंस की तरफ से डील कर रहे एजेंटो ने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल खरीदने का ऑफर दिया था। कथित रूप से यह सौदा दिसंबर 2009 में चेंगदू में हुई जहां चीनी एजेंटों द्वारा भारतीय विद्रोही ग्रुप को मिसाइल देने के एवज में 10 लाख डॉलर की मांग की गई, साथ में इसके इस्तेमाल के लिए तकनीकी प्रशिक्षण देने की भी पेशकश की गई। हालांकि, यह कहा जा रहा है कि वह डील हो नहीं पाया क्योकि विद्रोही ग्रुप इतना पैसा जुटा नहीं पाई। शिमरे ने इस बात का भी खुलासा किया कि चीनी सहयोग के बदले में नगा विद्रोही उन्हें अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सेना और मिसाइलों की तैनाती की सही जानकारी दिया करते हैं। यदि इन तथ्यों पर विश्वास किया जाए तो शिमरे के खुलासे से भारतीय आंतरिक मामलों में चीन की बढ़ती दखलंदाजी का पता चलता है। चीन बार–बार यह कहता है कि वह भारत के आंतरिक मसलों में हस्तक्षेप नहीं करता और अपने पूर्व चीनी प्रधानमंत्री द्वारा भारत के साथ 1954 में शांति और सद्भावना के लिए किये गये पंचशील समझौते का पालन करता है। लेकिन चीन अब भी भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। दक्षिण सीमाओं पर चीन की हरकतें और वहां की विद्रोही ग्रुप के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने और भारत का प्रभाव कम करने की उसकी साजिष की वजह से उसपर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है।

नेशनल काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन) की स्थापना 1980 की शुरुआत में इसाक चीसी सू थींगलेंग मुइवा और एस. एस खाप्लांग द्वारा की गई थी। इस संगठन की स्थापना दरअसल नगा नेशनल काउंसिल द्वारा भारत सरकार के साथ हुए शिलांग समझौते के विरोध के रूप में की गई थी। 1988 में एनएससीएन का विभाजन हो गया। एनएससीएन (के) प्रमुख खाप्लांग बने, जबकि एनएससीएन–आईएम के प्रमुख बने इसाक और मुइवा।

नगा विद्रोहियों को चीन का समर्थन कोई नया नहीं है। 1962 में चीन–भारत के युद्ध के बाद और पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से स्वयंभू नगा प्रधानमंत्री कुघाटो सुखई ने चीनी नेताओं को लिखे पत्र में भारत द्वारा उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ उनका समर्थन करने और किसी दबाए और कुचले हुए राष्ट्र का समर्थन करने की गुहार की। नवंबर 1966 में चीन ने 300 नगा विद्रोहियों के एक दल को अपने यहां आंदोलन के लिए हथियार उपलब्ध कराने के साथ प्रशिक्षित भी किया। जनवरी 1968 में वह दल वापस लौटा और उसने जस्टोमा जंगल में एक बड़ा कैंप लगाया। जब उन जगहों पर भारतीय सेनाओं ने हमला किया तो उन्हें चीनी हथियार और चीन के साथ उनके संबंध बताने वाले कुछ कागजात भी मिले। 1988 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चीन यात्रा के बाद चीन ने 1980 में विद्रोहियों को समर्थन देने की अपनी गतिविधियों में कमी लानी शुरू की। हालांकि, भारतीय सेना को विद्रोही संगठनों को चीनी एजेंसियों द्वारा सहयोग जारी रहने का शक बना हुआ है, लेकिन उसके पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं।

शिमरे से पूछताछ में उसने जो खुलासे किये वह भारतीय सुरक्षा अधिकारियों के लिए आश्चर्यजनक था। चीनी खुफिया एजेंसियों और एनएससीएन–आईएम के बीच इतने व्यापक स्तर पर सांठ–गांठ है कि वह सचमुच हैरत में डालने वाला है। इसमे यह पता चला कि वे अपने अधिकतर ऑपरेशन के लिए नेपाल, बांग्लादेश, थाइलैंड और उत्तरी कोरिया के नेटवर्क और बिचौलियों का इस्तेमाल करते हैं। शिमरे ने खुलासा किया कि उसने सबसे पहले 1994 में भारतीय विद्रोही ग्रुप नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के साथ संयुक्त हथियार समझौते के लिए चीन का दौरा किया था।

इस दौरान हथियार और युद्ध के अन्य साजो–समान की व्यवस्था चीनी सिविल डिफेंस कंपनी नॉरिनको (एनआरआईएनसीओ) ने की थी और इसमें 1800 हथियार, एके सीरीज के राइफल्स, एम16 ऑटोमेटिक एसॉल्ट राइफल्स, मशीन गन, स्नीपर राइफल्स और रॉकेट लांचर आदि शामिल थे। 1996 में उत्तर कोरिया के पानी जहाज का इस्तेमाल करके बीजिंग से बांग्लादेश तक फिर युद्धक हथियार मंगाय गये। जो ट्रक से होकर आखिर में भारतीय सीमा के अंदर एनएससीएन–आईएम के मुख्यालय तक पहुंचा था। इस मामले में बैंकॉक निवासी विली नारू को मुख्य मध्यस्थ माना जा रहा है जिसने इन सारे हथियार सौदों के लिए बिचौलिए की भूमिका निभाई। दिल्ली में एनएससीएएन–आईएम नेताओं द्वारा संगठन के हथियार और युद्धक क्षमता को बढ़ाने का फैसला करने के बाद शिमरे ने नारू के सहयोग से 2007 में कथित तौर पर

लेख के अनुसार, "भारत ने 'दक्षिणी तिब्बत' में अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग विमान तैनात कर रखे हैं और उसने उन्नत सुखोई–30 एमकेआई विमान उड़ाने की क्षमता वाले एयरपोर्ट का निर्माण किया है।'दक्षिणी तिब्बत' में भारतीय सैनिकों की कुल संख्या 2 लाख से ज्यादा हो गई है।"

दक्षिणी तिब्बत में भारत द्वारा अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती को चीन के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैयार किए जा रहे सैन्य ढांचे की प्रतिक्रिया मानी जा रही है। चीन ने नियंत्रण रेखा के पास कम से कम छह एयरपोर्ट और हथियारों की ढुलाई करने लायक एक सामरिक राजमार्ग तैयार किया है।

चीन से इन हथियारों का प्रबंध किया। यह माना जा रहा है कि नारू ने ही बैंकॉक में युथूना नाम के एक व्यक्ति से शिमरे की मुलाकात करवाई। युथूना दरअसल बैंकांक में टीसीएल का चीनी प्रतिनिधि था। टीसीएल, चीनी हथियार कंपनी चाइना शिंसिदाई की सहयोगी कंपनी है।

शिंसिदाई के वेबसाइट के अनुसार यह चीनी रक्षा उद्योग और साधारण नागरिक उत्पादों के निर्यात और आयात सौदों को अंजाम देती है। इस खरीदारी में 600 एके सीरीज के राइफल, 6 लाख युद्धक हथियार, 200 सब–मशीन गन, पिस्तौल, रॉकेट लांचर, हल्के मशीन गन और 200 किलोग्राम आरडीएक्स आदि शामिल हैं। करीब 12 लाख डॉलर के इस सौदे को चीन के बेइई बंदरगाह पर लोड किया गया एवं बैंकॉक के शिपिंग एजेंट द्वारा बांग्लादेश के कॉक्स बाजार भेजा गया। इस पूरे सौदे की प्रक्रिया और उसमें सूचनाओं और अन्य जानकारियों का आदान–प्रदान एक ई–मेल अकाउंट के माध्यम से हुआ एवं उसका लॉगइन और पासवर्ड विली नारू, दिल्ली और नगालैंड के नगा नेताओं और चीनी खुफिया एजेंसी के संचालकों के पास था।

माना जा रहा है कि पिछले सितम्बर में गिरफ्तार होने से एक सप्ताह पहले तक शिमरे विली नुरु से हथियार खरीदने और उसके साथ बातचीत की प्रक्रिया में शामिल रहा है। उसने यह भी कहा कि हथियारों की खरीद की एक ऐसी ही बातचीत अरुणाचल प्रदेश के लिए भी जारी है। इतना ही नहीं शिमरे ने सप्लायर्स से हथियार को चीन के रास्ते अरुणाचल के उपरी हिस्से में पहुंचाने के लिए कहा था। जांच एजेंसी शिमरे के अक्टूबर माह में किये गये गुप्त दौरे को भारत में हथियार सौदे के रूप में देख रही है।

चीन और एनएससीएन–आईएम के बीच संबंध के गहरे होने कारण क्या है? इस बारे में एक जानकारी यह मिली है कि 2008 में चीन ने युन्नान प्रांत के कुनमिंग के बाहर एनएससीएन–आईएम के एक स्थायी प्रतिनिधि की मेजबानी करने की स्वीकृति दी। शिमरी के अनुसार मुईवा ने वरिष्ठ चीनी खुफिया अधिकारियों को एक पत्र लिखा था जिसमें नगालैंड के सेमा जनजाति के 60 वर्षीय खोलोसे स्वू सुमी को चीन में एनएससीएन–आईएम का स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्ति की बात कही गई थी, जिसे चीन ने स्वीकार कर लिया था। इसके साथ ही खोलोसे चीन के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गया जो चीनी अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत कर भारत सरकार के साथ चल रही बातचीत और उसकी सेनाओं की गतिविधियों की जानकारी देता रहता है।

खोलोसे कथित तौर पर कीमती पत्थरों का व्यापारी था। वह एक यात्रा के दौरान शिमरे और उसकी पत्नी से कुमिंग हवाई अड्डे पर मिला। उसने उसकी मुलाकात चीनी खुफिया अधिकारियों से कराई, जिसमें चांग नामक व्यक्ति भी था जो देहोंग प्रांत पश्चिमी युन्नान के खुफिया विभाग का प्रमुख था। इसके अलावा शिमरे ली वुएं से भी मिला जो कि युन्नान प्रांत का खुफिया प्रमुख था। मुलाकात में उन लोगों से एनएससीएन आईएम के लिए सहायता और सहयोग की मांग की गई।

एनएससीएन–आईएम को समर्थन देने के लिए चीन के पास हथियार बेचने के अलावा भी कई कारण हैं। एक तो नगालैंड–अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र जिसके लिए भारत और चीन लगातार अपनी संप्रभुता के दावे करते हैं। दशकों से दोनों देशों के सैनिक इस क्षेत्र के वास्तविक सीमा को लेकर चूहे – बिल्ली के खेल में शामिल हैं। भारतीय सीमा में घुसपैठ करके चीन, सीमा विवाद में सौदेबाजी करने की सोच रहा है। इसके अलावा, चीन भारत के तेज विकास के कारण बने सहकर्मी और प्रतियोगी रूप को देखकर परेशान और सावधान है।

यह बात अब खास महत्व रखती है कि दोनों देश अपने इस सीमा विवाद का अंत करने के लिए लगातार प्रयासरत रहें। 1990 के प्रारम्भ से बीजिंग और नई दिल्ली सीमा विवाद को सुलझाने के लिए प्रयासरत हैं। ये विवाद दोनों के लिए ही लिटमस टेस्ट साबित हो रहा है। अगर भारतीय सेना एनएससीएन–आईएम को चीनी हथियार बेचने कि बात साबित कर देती है तो नई दिल्ली इस बात को काफी जोरदार तरीके से उठाते हए चीन को इस समस्या के समाधान के लिए गंभीर रूख नहीं अपनाने के लिए कठघरे में खड़ा कर सकता है।

एनएससीएन–आईएम के साथ चीनी गठजोड़ की वजह से भारत और बीजिंग के साथ मधुर संबंध बनाने के प्रयासों पर रोक लग सकती है। चीनी खुफिया एजेंसियों द्वारा भारत और एनएससीएन–आईएन के बीच शांति प्रयासों के मद्देनजर बातचीत की प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए कई प्रयास किये जा सकते हैं और ये विद्रोही ग्रुप के जरिए भारत–चीन सीमा पर भारतीय सेना के गतिविधियों की जानकारी ले सकता हैं।

हाल ही में भारतीय सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किए जांच में पता चला है कि चीन इन विद्रोही ग्रुपों को हथियारों और धन की आपूर्ति किसी अन्य देश के माध्यम से कराता रहा है। हालांकि, चीन सबूतों को भी नकार सकता है और यह कह सकता है कि ये हथियार ब्लैक मार्केट में चीनी हथियार निर्माताओं द्वारा चोरी छुपी बनाये गए हैं और इन विद्रोही संस्थाओं का संबंध पाकिस्तान, बर्मा या बांग्लादेश से है। ऐसा कह कर चीन अपना बचाव कर सकता है। इस

संबंध में शिमरे का खुलासा निश्चित रूप से भारतीय अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण है।

चीन ने कहा, भारत ने अरुणाचल में किया है घुसैपठ

(यूरेशिया रीव्यू, 21 मार्च)

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण वाले ग्लोबल टाइम्स ने 4 मार्च, 2011 को अपने 'चर्चा मंच' स्तंभ के चीनी भाषा संस्करण 'हुआनकी' में जाओ एन का एक ब्लॉग लेख प्रकाशित किया है। एन के इस लेख का शीर्षक है "दक्षिणी तिब्बत में अपनी सेनाओं की संख्या बढ़ाकर भारत ने एक चुनौती पेश की है, क्या चीन से युद्ध की तैयारी है।"

इस लेख में आरोप लगाया गया है कि स्थानीय पुलिस और सशस्त्र बलों के अलावा भारत के तीन पर्वतीय डिवीजन और एक टोही बटालियन की तैनाती उस इलाके में की गई है जिसे चीन 'दक्षिण तिब्बत' (भारत का अरुणाचल प्रदेश) मानता है। लेख के अनुसार, "भारत ने 'दक्षिणी तिब्बत' में अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग विमान तैनात कर रखे हैं और उसने उन्नत सुखोई–30 एमकेआई विमान उड़ाने की क्षमता वाले एयरपोर्ट का निर्माण किया है। 'दक्षिणी तिब्बत' में भारतीय सैनिकों की कुल संख्या 2 लाख से ज्यादा हो गई है।" इस ब्लॉग के लेखक जाओ एन कहते हैं, "भारतीय उच्चाधिकारियों ने बार–बार यह बयान दिए हैं कि भारत चीन के साथ दूसरे युद्ध में नहीं हारेगा। कश्मीर से अपने कुछ सैनिकों को हटा लेने के पीछे भारत की सोच यह है कि वह पाकिस्तान के साथ मेल–मिलाप करना चाहता है और अफगानिस्तान एवं ताजिकिस्तान में अपनी सेना भेजने की भी भारत की आकांक्षा बढ़ रही है।"

जाओ एन ने यह स्वीकार किया है कि चीन के दक्षिण–पश्चिम में भारत की गतिविधियां दोनों देशों के बीच बवाल की जड़ इसलिए नहीं बन पाईं, इसकी मुख्य वजह यह है कि अभी इसके लिए समय नहीं आया है। चीन में अब भी पर्याप्त आंतरिक क्षमता है और वह अपनी रक्षा करने की सहज काबिलियत रखता है। अमेरिका के नेतृत्व में कई देश एक प्रकार की अस्थिरता का सामना कर रहे हैं, इसलिए चीन को घेरने के किसी भी षडयंत्र को विफल होना ही है। लेखक का कहना है कि इन कारकों ने भी भारत को अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने और अपनी महत्वाकांक्षा को एक 'विस्फोटक' स्तर तक फैलाने से नहीं रोका है। इसके विपरीत चीन दक्षिणी तिब्बत के मसले पर बातचीत का ही सहारा लेने की कोशिश कर रहा है। भारत की जीडीपी इस साल बढ़ जाएगी और शायद वह चीन से भी ज्यादा हो जाए, इसके साथ ही अगले पांच साल में भारत की आबादी चीन से भी ज्यादा हो सकती है।" इस ब्लॉग में कहा गया है कि कई कारकों से प्रोत्साहित होकर ऐसा हो सकता है कि भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षी से होश खो बैठे और वह चीन पर 'हमला बोल दे।'

'दक्षिणी तिब्बत' के उस इलाके पर भारत के अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने की कार्रवाई को किस रूप में समझा जा सकता है, जिस पर चीन की प्रभुसत्ता है। इस सवाल को उठाते हुए लेख में कहा गया है कि भारत की कार्रवाई अब उसकी आत्मरक्षा की जरूरतों तक ही सीमित नहीं है। यह बात ऐतिहासिक रूप से साबित हो चुकी है कि 'दक्षिणी तिब्बत' चीन का हिस्सा है और यह इलाका चीन की कई पीढ़ियों के लोगों के सपने में बसा हुआ है। लेकिन करीब 10 करोड़ की जनसंख्या वाला यह 'दक्षिणी तिब्बत' वास्तव में भारत के नियंत्रण में है। लेख में कहा गया है कि ऐसी परिस्थिति में "हमें यह देखना चाहिए कि भारत वास्तव में दक्षिणी तिब्बत का विकास नहीं करना चाहता, बल्कि वह एसे एक ऐसे स्प्रिंगबोर्ड के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है जहां से वह चीन के भीतरी इलाकों में जंप लगा सके। जाओ एन इस बात पर भी ध्यान आकर्षित करते हैं कि सबसे ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि दक्षिणी तिब्बत फिर से भारत की चढ़ाई का शिकार हो गया है। ऐसी स्थिति में चीन के लिए यह संभव नहीं होगा कि वह शांतिपूर्ण तरीके से दक्षिणी तिब्बत को 'फिर से हासिल करे'। इस परिस्थिति को और गंभीर बनाने से रोकने के लिए चीन ने यह साफ किया है कि वह हथियारों का सहारा नहीं लेगा और भारत इस बात को अच्छी तरह से समझता भी है। दक्षिणी तिब्बत में भारत द्वारा अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती को चीन के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैयार किए जा रहे सैन्य ढांचे की प्रतिक्रिया मानी जा रही है। चीन ने नियंत्रण रेखा के पास कम से कम छह एयरपोर्ट और हथियारों की ढुलाई करने लायक एक सामरिक राजमार्ग तैयार किया है। लेख में कहा गया है, "वैसे तो जमीनी स्तर पर यह दिख रहा है कि भारत ने दक्षिणी तिब्बत में नए सैनिकों को भेजा है, लेकिन यह चरण सिर्फ एक खोजबीन वाला हमला हो सकता है, लेकिन खोजबीन वाला यह हमला बाद में पूरे हमले में बदल सकता है। महत्वपूर्ण समय पर भारत चीन के खिलाफ परमाणु हथियारों का भी सहारा ले सकता है। यह संभव नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और भारत द्वारा चीन के बहुमूल्य इलाके पर कब्जा करने के लिए हो रहे सैन्य और हथियारों का इस्तेमाल देखते रहें। इस तरह हम एक ऐसे भारत को देख रहे हैं जो चीन को हराने के एकमात्र इरादे से आक्रामक हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा जमीन हड़प रहा है और एक नए महान हिंदुस्तान को नए सिरे से स्थापित कर रहा है।"

पहले चरण को 'कम तीव्रता वाले युद्ध की हालत बनाए रखने' वाला चरण मानते हुए इसमें कहा गया है कि देश की लघु और दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए चीन सरकार को भारत के साथ संबंधों में अब सौहार्द का रास्ता छोड़ देना चाहिए, इसकी जगह चीन सरकार को अपनी सहनशीलता की एक सीमा तय करनी चाहिए।

दूसरी तरफ, चीन दक्षिणी तिब्बत को एक विवादास्पद क्षेत्र मानता है। इस संदर्भ में दो सवाल उठते हैं–क्या इस तरह की स्थिति चीन के लिए फायदेमंद है। क्या अमेरिका द्वारा भारत को समर्थन करने से चीन एक कमजोर स्थिति में आ गया है।

दलाई लामा की भूमिका की चर्चा करते हुए जाओ एन कहते हैं, "वह बूढ़े हो रहे हैं और अपने उत्तराधिकारी की तलाश के सिलसिले में एक नाजुक स्थिति में पहुंच गए हैं। वह एक 'वृहद तिब्बत' की स्थापना कर इसे भारत को बेच देना चाहते हैं। जब वह 100 साल के होंगे तब वह शायद वह अपनी 'दलाई लामा रेखा' बना सकें जैसे कि पहले 'मैकमोहन रेखा' खींची गई है, लेकिन इस शर्त पर कि 'वृहद तिब्बत' का भारत में विलय कर दिया जाए।"

इसके बाद यह लेख एक सवाल उठाता है–" भारत स्वर्गीय मैकमोहन द्वारा खींची गई रेखा का इस्तेमाल चीनी जमीन को हथियाने में कर रहा है और क्या भारत इसी प्रकार एक बार फिर स्वर्गीय दलाई लामा रेखा के आधार पर चीन की जमीन हथियाएगा ! यह मानते हुए कि दलाई लामा अब भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास इतना प्रभाव और क्षमता है कि चीन को धोखा दे सकें, लेख में कहा गया है कि भारत सरकार निर्वासित तिब्बतियों की सरकार को 'मान्यता' देती है, इसकी वजह से ही निकट भविष्य में चीन और भारत के बीच जंग छिड़ सकती है।

चीन को एक सलाह देते हुए इस ब्लॉग में कहा गया है, "ऐसी परिस्थिति में जब हम चीन के दक्षिणी तिब्बत इलाके में भारत की निर्लज्ज घुसैपठ का सामना कर रहे हैं, चीन को कम से कम एक तीन चरणों वाली योजना तैयार करनी चाहिए।" पहले चरण को 'कम तीव्रता वाले युद्ध की हालत बनाए रखने' वाला चरण मानते हुए इसमें कहा गया है कि देश की लघु और दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए चीन सरकार को भारत के साथ संबंधों में अब सौहार्द का रास्ता छोड़ देना चाहिए, इसकी जगह चीन सरकार को अपनी सहनशीलता की एक सीमा तय करनी चाहिए। लेख में कहा गया है कि 'कम तीव्रता वाले युद्ध की हालत बनाए रखने' का दौर सिर्फ तीन से पांच साल का हो सकता है क्योंकि एक बार भारत की जनसंख्या और आर्थिक वृद्धि दर चीन से ज्यादा हुई तो यह उभरता भारत दक्षिण एशिया में अपनी भूमिका से संतुष्ट नहीं होगा और वह निश्चित रूप से चीन को चुनौती देगा।

इस प्रकार के कम तीव्रता वाले प्रतिरोध को जारी रखते हुए चीन को इस बात की गारंटी रखनी चाहिए कि उसकी सैन्य श्रेष्ठता सबसे ज्यादा स्तर तक हो, साथ ही इस बात का भी प्रयास करना चाहिए चीन बड़े पैमाने पर भारत पर बम या अन्य तरीके से हमला कर सके। चीन यदि भारत के खिलाफ मजबूत प्रतिरक्षा क्षमता हासिल कर लेता है तो भारत दक्षिणी तिब्बत में वह सब नहीं कर सकता जो वह चाहता है। अन्यथा भारत ताकत जुटाता जाएगा, लगातार चीन की सेनाओं को दबाता जाएगा ताकि दक्षिणी तिब्बत के ऊपर अपना ज्यादा से ज्यादा प्रभुत्व बनाए रख सके।

इस ब्लॉग में लिखे लेखों के अनुसार चीन की दूसरी योजना वास्तव में भारत के खिलाफ एक कम तीव्रता वाले लड़ाई की होनी चाहिए। दक्षिणी तिब्बत पर अपनी प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए इस तरह के 'कम से कम सीमा' वाली योजना को चीन भारत के खिलाफ एक 'मध्यम तीव्रता के युद्ध' में बदल सकता है, ताकि दक्षिणी तिब्बत को हड़पने के भारत के षडयंत्र को कम से कम समय में नेस्तनाबूद किया सके और दक्षिणी तिब्बत को चीन के व्यावहारिक कब्जे में लाया जा सके। इससे चीन वहां तेज आर्थिक विकास कर सकेगा और इससे वहां के लोगों का काफी हद तक दिल जीता जा सकेगा। इस तरीके से चीन–भारत विवाद खत्म हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी।

ब्लॉग के अनुसार चीन की तीसरी योजना का उद्देश्य भारत के साथ एक लंबी लड़ाई की शुरुआत हो सकता है, इस तरीके से भारत के विघटन की शुरुआत की जा सकती है। चीन सिलीगुड़ी रेखा के समानान्तर भारत से पूरे उत्तर–पूर्व हिस्से को पूरी तरह से अलग कर सकता है। इस तरीके से इन इलाकों में सक्रिय अलगाववादी ताकतों का इस्तेमाल करके एक पूरी तरह से नया 'पूर्वी हिंदुस्तान' बनाया जा सकता है। साथ ही, चीन इस नए उभरे हुए देश के लिए म्यांमार, बांग्लादेश आदि की मदद भी ले सकता है। इस तरीके से भारत को इन क्षेत्रों के मामले से पूरी तरह से दूर किया जा सकता है।

लेख में कहा गया है कि भारत दक्षिणी तिब्बत के अपना अभिन्न हिस्सा होने का दावा करता है। दूसरी तरफ, चीन दक्षिणी तिब्बत को एक विवादास्पद क्षेत्र मानता है। इस संदर्भ में दो सवाल उठते हैं–क्या इस तरह की स्थिति चीन के लिए फायदेमंद है। क्या अमेरिका द्वारा भारत को समर्थन करने से चीन एक कमजोर स्थिति में आ गया है। जाओ एन ने इन सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि अमेरिका से मिल रहे सैन्य सहायता और तकनीकी समर्थन के बदले भारत दोनों देशों के साझा दुश्मन चीन के साथ निपटने में कड़ा रवैया अख्तियार करना चाहेगा। दूसरी तरफ, चीन ने क्विंघई–तिब्बत रेलवे लाइन जैसे बुनियादी ढांचे का विकास किया है लेकिन उसका सैन्य इरादा नहीं है और वह हमलों को आगे बढ़ाने की योजना नहीं बनाना चाहता। बुनियादी ढांचा नागरिक इस्तेमाल के लिए है, लेकिन युद्ध के समय उसका इस्तेमाल सैन्य जरूरतों के लिए किया जा सकता है।